



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 611]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 5, 2004/आषाढ़ 14, 1926

No. 611]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 5, 2004/ASADHA 14, 1926

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क के आयुक्त का कार्यालय

अभिसूचना

रायपुर, 16 जून, 2004

सं. 04/2004 (एन. टी.)

(सीमा शुल्क)

का.आ. 799(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 45(1) के तहत सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एच. के. जैन, आयुक्त, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, रायपुर एतद्वारा मैसर्स कंटेनर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) को इनलैन्ड कंटेनर डीपो (आई सी डी) कापा, रायपुर में कंटेनरों में प्राप्त आयातित माल तथा/या आई सी डी, कापा, रायपुर में वाहनान्तरित आयातित, माल को, जब तक कि बरेलू खपत या माल गोदाम में रखने के लिये इनकी निकासी नहीं कर दी जाती या सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अध्याय VIII के उपबंधों के अनुसार इनको वाहनान्तरित नहीं कर दिया जाता तब तक के लिये कस्टोडियन के रूप में नियुक्त करता हूँ। इसी प्रकार मैसर्स कंटेनर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, आई सी डी, कापा, रायपुर में भरने, गिनने, सीमा शुल्क परीक्षण करने, परिवहन तथा आगे के लदान के लिये गेटवे पोर्ट तक सीमा शुल्क की सील लगे हुए कंटेनरों को सुरक्षित रूप से पहुंचाने के लिए लाये गए निर्यात माल के लिये भी कस्टोडियन रहेंगे।

निर्यात एवं आयात किये जाने वाले माल के लिये कस्टोडियन के रूप में मैसर्स कंटेनर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 45(2) के उपबन्धों तथा उपरोक्त विषय पर समय-समय पर जारी नियमों, विनियमों एवं निर्देशों का पालन करना होगा।

सीमा शुल्क क्षेत्र में उतारे जाने के बाद कस्टोडियन की अभिरक्षा में रहते हुए यदि किसी भी आयातित माल की कोई चोरी होती है अथवा उसका कोई नुकसान होता है तो सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 45(3) के अनुसार मैसर्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को ऐसे माल पर धारा 30 के अन्तर्गत उस परिवहन के आगमन के लिये जिसमें कथित माल को लाया गया था, के संबंध में समुचित अधिकारी को, किसी भी इम्पोर्ट मेनिफेस्ट या इम्पोर्ट रिपोर्ट, जैसी भी स्थिति हो, की डिलीवरी की तिथि को लागू दर से शुल्क अदा करना होगा।

प्रारंभ में यह नियुक्ति 5 वर्ष के लिये रहेगी एवं आयुक्त की संतुष्टि पर निर्भर करेगी। आयुक्त को यह अधिकार रहेगा कि विशिष्ट कारण बताते हुए एवं उसके स्पष्टीकरण का कस्टोडियन को अवसर देते हुए इस नियुक्ति को किसी समय समाप्त कर दें। उसके बाद प्रत्येक पांच वर्ष पर इस नियुक्ति की समीक्षा की जायेगी।

[फा. सं. VIII (सी.) 48-02/2004/के.उ.सु./तक.]

एच. के. जैन, आयुक्त

## OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE AND CUSTOMS

## NOTIFICATION

Raipur, the 16th June, 2004

No. 04/2004 (N.T.)

## (CUSTOMS)

S. O. 799(E).—In exercise of the powers conferred upon me under Section 45(1) of the Customs Act, 1962, I, H.K. Jain, Commissioner, Customs & Central Excise, Raipur, hereby appoint M/s Container Corporation of India Ltd. (A Govt. of India Undertaking) to be the Custodian of imported goods received in containers at the Inland Container Depot (ICD), Kapa, Raipur and/or transhipped to ICD, Kapa, Raipur until these are, cleared for home consumption or warehoused or are transhipped in accordance with the provisions of Chapter VIII of the Customs Act, 1962. Similarly M/s. Container Corporation of India Ltd. will also be the Custodian of the export goods brought into ICD, Kapa, Raipur for stuffing, accountal, Customs examination, Transportation and safe delivery of the Customs scaled containers at the gateway port for onward shipment.

M/s. Container Corporation of India Ltd. as the custodian of the goods meant for export and import would be required to comply with the provisions of Section 45(2) of the Customs Act, 1962 as well the rules, regulations and instructions issued from time to time on the subject mentioned above.

If any imported goods are pilfered or lost after unloading in the Customs area while in the custody of custodian, then in terms of Section 45(3) of the Customs Act, 1962, M/s. Container Corporation of India Ltd. shall be liable to pay duty on such goods at the rate prevailing on the date of delivery of any import manifest, or as the case may be, an import reoprt, to the proper officer under Section 30 for the arrival of the conveyance in which the said goods were carried.

This appointment shall initially remain for 5 years and subject to the satisfaction of the Commissioner. The Commissioner shall have the right to terminate this appointment at any time after assigning specific reasons and giving an opportunity for the custodian to explain his case. The appointment shall be reviewed after every five years thereafter.

[F. No. VIII (CUS) 48-02/2004/CX/Tech.]

H. K. JAIN, Commissioner